क्या नीति आयोग एक नई बोतल में पुरानी शराब के समान है?

लेखक - अरुण मायरा (पूर्व सदस्य, योजना आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र- II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

10 जून, 2019

"इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि थिंक टैंक ने अपने घोषणापत्र में वर्णित नई भूमिका को अपना कर क्या-क्या हासिल किया है।"

इस बार भी भारत के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। अब समय आ गया है कि सरकार रोजगार और आय बढ़ाने की जरूरतों पर निवेश और विकास को पुनर्जीवित करने पर वित्तीय क्षेत्र को सुलझाने पर उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक बेहतर दिशा प्रदान करने पर खराब शिक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरण, प्रदूषण तथा पानी की कमी की बढ़ती समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दे। भले ही चुनाव के समय सांख्यिकीय भ्रम पैदाकर के बेरोजगारी और विकास की गंभीर समस्याओं की बात से इनकार किया गया था, लेकिन इनसे निपटने के लिए वर्तमान में उच्चस्तरीय कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है।

भले ही हमे इस बात से फर्क ना पड़े कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती जीडीपी है या नहीं, लेकिन हमे इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक समावेश को प्राप्त करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बहाल करने के लिए हमे एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत की समस्याएँ जटिल हैं, क्योंकि वे सभी परस्पर संबंधित हैं। सिस्टम के केवल एक हिस्से को ठीक करने से मामला और बदत्तर हो सकता हैं। उदाहरण के लिए, रोजगार के पर्याप्त अवसर के बिना लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। कार्य की जटिलता एक अच्छी योजना और एक अच्छी रणनीति की मांग करती है।

जाँच के दायरे में

अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार के पास अपनी जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी योजना और रणनीति बनाने की क्षमता है? चूंकि भारत ने अधिक समावेश और स्थिरता के साथ तेजी से विकास नहीं किया है, इसलिए कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भारत ने अभी तक अपेक्षित क्षमताओं को विकसित नहीं किया हैं। और श्री मोदी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं। दरअसल, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में, जो पहले बड़े सुधार की घोषणा की थी। वह योजना आयोग को खत्म करने से संबंधित था। उन्होंने इसे 'नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (NITI Aayog) शीर्षक के साथ बदल दिया।

अब, जब देश की अर्थव्यवस्था ने श्री मोदी द्वारा बनाई गई उच्च अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया और नागरिकों को 'अच्छे दिन' का एहसास नहीं हुआ, तो नीति आयोग का प्रदर्शन जाँच के अधीन आना अपेक्षित था, जो उचित भी है। बहुत से लोग उदासीन रूप से योजना आयोग को याद कर रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी थे, जो इसकी बहुत आलोचना कर रहे थे और चाहते थे कि इसे हटा दिया जाए।

श्री मोदी के पूर्ववर्तियों, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, बड़ी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया था। जब वाजपेयी को अर्थव्यवस्था की वृद्धि को 9% तक बढ़ाने के लिए एक वैश्विक थिंक-टैंक द्वारा नौ-सूत्री योजना प्रस्तुत की गई थी, तो उन्होंने कहा, "हम सब जानते हैं।

सवाल यह है कि यह सब कैसे होगा? "उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई हितधारकों को एक बड़े, विविध और लोकतांत्रिक देश-राज्यों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और यहाँ तक कि राजनीतिक विपक्ष-को एक योजना के कार्यान्वयन में शामिल होना चाहिए। इसलिए, यह योजना के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके सहकारी कार्यान्वयन के लिए भी एक रणनीति होनी चाहिए।

डॉ. सिंह ने घोषणा की, कि योजना आयोग में सुधार लंबे समय से रुका हुआ था। इसके लिए कई हितधारकों से परामर्श किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की जाँच की गई। डॉ. सिंह के शब्दों में, एक पर्याप्त रूप से सुधारित संस्थान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के बजाय 'सिस्टम सुधार' की क्षमता होगी और जिसमें बजट उपलब्ध कराए बिना 'अनुनय की शक्ति' होगी।

सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक आयोग, जो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, ने बजटीय प्रक्रियाओं, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के बीच जिम्मेदारियों के विभाजन और 'योजना' और-गैर-योजना व्यय'के बीच अंतर की जाँच की। जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि बजटीय जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय में केंद्रित होनी चाहिए और यह योजना आयोग के लिए वित्तीय प्रावधानों के लिए शक्तियों के लिए वांछनीय नहीं था।

योजना आयोग में कुछ लोग चिंतित थे कि अगर वित्तीय शक्ति न हो तो उनकी स्थिति बिना दांत वाले शेर के समान हो जाएगी। वह अन्य राज्यों को जो वे चाहते है उसके लिए कैसे राजी करेगा? मुख्यमंत्रियों ने कहा कि योजना आयोग को अपनी आवश्यकताओं को समझने और उन विचारों को विकसित करने की क्षमता में सुधार करना चाहिए, जिन्हें वे अपनाना चाहते हैं। श्री मोदी, एक शक्तिशाली मुखिया के रूप में, योजना आयोग की क्षमताओं की सीमाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हें खुद इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

एक अच्छी शुरुआत

आमूल परिवर्तन का कार्यान्वयन कभी भी आसान नहीं होता है। यदि चीजें जल्द ही ठीक नहीं होती हैं, तो पुरानी स्थिति के लिए उदासीनता बढ़ जाएगी साथ ही इससे असंतोष भी व्याप्त हो जाएगा और परिवर्तन करने वाले को विघटन के लिए दोषी ठहराया जाएगा। नीति आयोग की घोषणापत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के शासन को बदलने में एक नई यात्रा के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है।

नीति आयोग और सरकार को नीति आयोग द्वारा अपने घोषणापत्र में वर्णित नई भूमिका को अपनाने के लिए अब तक जो कुछ भी हासिल किया गया है, उसकी एक जाँच करनी चाहिए। और यह आकलन करना चाहिए कि क्या यह एक शक्तिशाली सिस्टम सुधारक और हितधारकों के प्रेरक बनने के लिए पर्याप्त रूप से अपनी क्षमताओं को रूपांतरित कर चुका है।

इस बात की गहरी चिंता है कि नीति आयोग ने सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में अपनी अखंडता खो दी है। यह सरकार का मुखपत्र और सरकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयनकर्ता बन गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि नीति आयोग में केंद्र और राज्यों में सरकार के कार्यक्रमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए।

कुछ लोग यह भी याद दिलाते है कि यूपीए-2 सरकार के अंतिम दिनों में स्थापित एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय को एनडीए सरकार ने बंद कर दिया था। कईयों का मानना है कि योजना आयोग के पास सभी के साथ एक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन था और जो अभी भी जारी है। वे नियोजन और परिवर्तन के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को याद करते हैं।

बाद के मूल्यांकन के पारंपरिक दृष्टिकोण संख्या, बजट और नियंत्रण के पुराने प्रतिमान से संबंधित है। नीति आयोग के चार्टर ने एक नई बोतल प्रदान की है। यह हितधारकों द्वारा सहकारी शिक्षण और सहकारी कार्यान्वयन के नए तरीकों की आवश्यकता को इंगित करता है, जो कि राजनीतिक या बजटीय प्राधिकरण के साथ तकनीकी विशेषज्ञों के किसी भी केंद्रीय निकाय द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

ऊपर से बजट, नियंत्रण और विशेषज्ञ समाधान के पुराने विचारों के साथ इस नई बोतल को भरने से भारत बदल नहीं जाएगा। नीति आयोग की प्रभावकारिता के बारे में बहस को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि यह नई भूमिका निभा रही है या नहींऔर इस भूमिका को निभाने के लिए क्षमताओं को प्राप्त करने में इसने क्या प्रगति की है।

GS World टीम...

नीति आयोग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी।
- डॉ. राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि गृहमंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे।
- इसके अलावा वी के सारस्वत, वी.के पॉल और रमेश चंद को फिर से सदस्य चुना गया है।

आयोग के बारे में

- 1 जनवरी, 2015 को इसकी स्थापना थिंक टैंक के रूप में की गयी थी।अस्तित्व में आए नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विजन एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है।
- केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देशभर से सुझाव आमंत्रित करके जन-भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियाँ बनाने का काम करता है।
- अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और उसके बाद योजना आयोग के भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया।
- नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना के अंतर्गत व्यय और गैर-योजनांतर्गत व्यय का अंतर समाप्त हो चुका है। अब केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धनराशि का हस्तांतरण केवल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग, योजना आयोग की भाँति भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक संविधानेत्तर निकाय होने के साथ ही एक गैर-वैधानिक (जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित न हो) निकाय भी है।

नीति आयोग की संरचना

- **भारत के प्रधानमंत्री:** अध्यक्ष
- गवर्निंग कांउसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होगें।
- विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलें, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए 'क्षेत्रीय परिषद' गठित की जायेगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जायेगी।
- भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। (इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे)
- संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जायेंगे।
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न होगें-
- **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **सदस्य:** पूर्णकालिक
- **अंशकालिक सदस्य:** अग्रणी विश्वविद्यालय शोध
- संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे।
- **पदेन सदस्य:** केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होगें। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी।
- मुख्य संचालन अधिकारी: भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

उद्देश्य

- नीति आयोग भारत की विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा।
- विकेन्द्रीकरण, भागीदारी, सांझेदारी, सहयोग, समन्वय के भावों के साथ शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए नीति आयोग के बैनर तले कार्य किया जायेगा।
- केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एकपक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जायेगा।
- नीति आयोग द्वारा राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा दिया जायेगा।
- नीति आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिये ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। आयोग निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **नीति आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था।
   2. यह योजना आयोग की भाँति भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है।
   3. इसके गवर्निंग कांउसिल में केवल राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) केवल 3
   (d) 1, 2 और 3

Q. Consider the following statements regarding the NITI Aayog.

1. It was formed in January 2015.
2. It is a body created by the Union Cabinet, like the Planning Commission.
3. In its governing council only the chief ministers of the states are included.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) Only 1
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- योजना आयोग की अपेक्षा नीति आयोग अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा है? इस सन्दर्भ में नीति आयोग के कार्यों की चर्चा करते हुए अपेक्षित सुधारों की व्याख्या कीजिए। (250 शब्द)

Q. How far did the NITI Aayog have been successful in its objectives than the Planning Commission? Explain the expected reforms while discussing the functions of the NITI Aayog in this context. (250Words)

नोट : 8 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

Committed To Ex